भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 422

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)

पीएलएफएस के अनुसार वेतनभोगी वर्ग की धीमी वृद्धि

422. श्री अखिलेश प्रसाद सिह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से यह जानकारी मिली है कि पिछले दशक में भारत के वेतनभोगी वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में **3** प्रतिशत से अधिक और शहरी क्षेत्रों में **1** प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई है**;**

(ख) यदि हां**,** तो धीमी वृद्धि के क्या कारण हैं**;** और

(ग) विगत पांच वर्षो में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार**,** वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वेतनभोगी वर्ग सहित 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की व्यक्तियों का रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)			
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
2017-18	48.1	43.9	46.8
2018-19	48.9	43.9	47.3
2019-20	53.3	45.8	50.9
2020-21	55.5	45.8	52.6
2021-22	55.6	46.6	52.9
2022-23	59.4	47.7	56.0
2023-24	62.1	49.4	58.2

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) पिछले वर्षों में बढ़ा है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

*****